C M Y K

www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 154 नागपुर, सोमवार, 1 मई 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

बुरी फंसी सोहा अली खान
लोकायुक्त ने दिया मामला दर्ज करने का आदेश

मुंबई

फिल्म एक्ट्रेस सोहा अली खान के सितारे इन दिनों गर्दिश में दिख रहे हैं। ठंडे बस्ते में जा चुके आर्म्स लाइसेंस के एक मामले में अचानक जांच और केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के लोकायुक्त ने सोहा को जारी किए गए आर्म्स लाइसेंस मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया। बताया जा रहा है कि सोहा को 1996 में आर्म्स लाइसेंस जारी किया गया था, उस वक्त उनकी उम्र 18 साल 1 महीना थी। जबकि लाइसेंस के लिए 21 साल की उम्र अनिवार्य है।

लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल (रि.) ने इस मामले की अगली सुनवाई की 24 जुलाई को तय की है। इसके साथ ही उन्होंने सीपी और एलए गुड़गांव को इस मामले में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की सुनवाई एनिमल एक्टिविस्ट नरेश कुमार कादियान की शिकायत पर हुई है। पिछले साल मार्च में कादियान ने लोकायुक्त से शिकायत करते हुए इस मामले की जांच की मांग थी, जिसमें कहा गया था कि आर्म्स लाइसेंस मिलने के वक्त सोहा की उम्र कम थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, काले हिरण का शिकार मामले में जांच के दौरान इसका खुलासा हुआ था। आरोप है कि नवाब मंसूर अली खान पटौदी ने 2006 में इस राइफल से झज्जर में काले हिरण का शिकार किया था। इस राइफल को जब्त कर लिया गया, लेकिन रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं था कि यह सोहा खान के नाम से दर्ज है। जांच में सामने आया था कि 12 बोर की यह राइफल पहले सुल्तान के नाम से दर्ज थी, जिसे बाद में सोहा अली खान के नाम किया गया था।

इस साल 10 मार्च को लोकायुक्त को सौंपी गई रिपोर्ट में रजिस्ट्रार ने कहा था कि सोहा अली खान को 18 से कम उम्र में ही आर्म्स लाइसेंस जारी कर दिया गया था, यह साबित हो चुका है। सोहा ने आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध किया, जिसके के लिए उन्हें सजा दी जानी चाहिए। 20 अप्रैल को सुनवाई करते हुए लोकायुक्त जस्टिस ने गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, झज्जर के एसपी और कलेक्टर सहित 5 लोगों को 24 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

सुकमा हमला : अब सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान खाना नहीं खाएंगे जवान

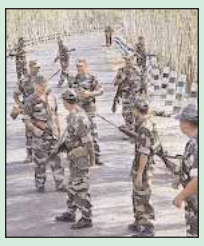

रायपुर

नक्सली मोर्चे पर सर्चिंग कर रहे जवानों द्वारा अब फील्ड में खाना खाने पर रोक लगा दी गई है। सीआरपीएफ के आला अधिकारियों की बैठक के बाद यह फरमान जारी किया गया कि कोई भी जवान ड्यूटी के दौरान खाना नहीं खाएगा। जवानों की ड्यूटी टाइम में बदलाव किया जाएगा। बताया जा रहा है कि नई टुकड़ी के मौके पर पहुंचने के बाद मोर्चे पर तैनात जवान वापस कैंप लौटेंगे और वहीं खाना खाएंगे। सीआरपीएफ के आला अधिकारियों ने बताया कि नक्सली मोर्चे पर सबसे ज्यादा मौत जवानों के खाना खाने के दौरान हुई हैं। इसको देखते हुए यह तय किया गया है कि जवान कैंप में वापस आने के बाद ही खाना खाएंगे। सूत्रों की मानें तो कुछ जवानों ने शिकायत की थी कि समय पर खाना नहीं मिलता है। अब तय किया गया है कि जवान छह घंटे ड्यूटी पर रहेंगे। छोटी-छोटी टुकड़ियां बनाई जाएंगी। फील्ड में तैनात जवानों को सिर्फ नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। एसओपी का पालन करते हुए सभी जवान एक साथ नाश्ता भी नहीं करेंगे। 20 फीसदी जवान नाश्ता करेंगे और 80 फीसद मोर्चे पर मुस्तैद रहेंगे।

'मन की बात' में पीएम ने दिया नारा
वीआइपी की जगह 'ईपीआइ'

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीआइपी संस्कृति पर एक बार फिर से जोर-शोर से बरसे हैं। उन्होंने देश से वीआइपी संस्कृति को हटाने के लिए ईपीआइ का नारा दिया है। ईपीआइ यानी हर व्यक्ति महत्वपूर्ण (एवरी परसन इज इंपोर्टेंट)। उन्होंने कहा है कि नेता-अफसरों की गाड़ियों से लाल बत्ती तो उन्होंने हटवा दी है, अब साझा प्रयास से इस मानसिकता को भी देश से हटा दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में वीआइपी संस्कृति को ले कर बेहद चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने कहा, एक नया इंडिया बनाना है। इसकी अवधारणा यह है कि यहां वीआइपी की जगह ईपीआइ का महत्व बढ़े। जब मैं वीआइपी की जगह ईपीआई कह रहा हूं तो ईपीआइ का मतलब है एवरी परसन इज इंपोर्टेंट। हर व्यक्ति का महत्व है, महात्म्य है। अगर 125 करोड़ देशवासियों का महात्म्य हम स्वीकार करेंगे तो महान सपनों को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी शक्ति एकजुट हो जाएगी। हम सब मिल कर यह करेंगे।

प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर माना कि देश में वीआइपी संस्कृति को ले कर आम लोगों के मन में काफी नफरत है। इसे देखते हुए हाल ही में केंद्र सरकार ने मौजूदा नियमों में संशोधन कर लाल बत्ती की व्यवस्था ही खत्म कर दी है। अपने इस फैसले के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, देश में वीआइपी संस्कृति के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा है, यह मुझे अभी-अभी अनुभव हुआ है।

जब सरकार ने तय कर दिया कि अब हिंदुस्तान में कितना ही बड़ा आदमी हो अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा कर नहीं घूमेगा। यह एक प्रकार से वीआइपी कल्चर का सिंबल बन गया है। अनुभव कहता है कि लाल बत्ती तो गाड़ी पर लगती थी, लेकिन धीरे-धीरे दिमाग में घुस जाती थी। दिमागी तौर पर वीआइपी कल्चर पनप चुका है। अभी तो लाल बत्ती गई है इसके लिए कोई यह दावा तो नहीं कर पाएगा कि दिमाग में जो लाल बत्ती घुस गई है, वह निकल गई होगी। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

नक्सलियों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' के लिए एनएसजी डोभाल ने संभाली कमान

रायपुर

छत्तीसगढ़ के सुकमा स्थित बुरकापाल में नक्सली हमले में 25 जवान खोने के बाद अब बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी है। गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, सुकमा में नक्सलियों से निपटने की कमान खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने संभाल ली है। डोभाल दो मई को दिल्ली से लेकर सुकमा तक नक्सल ऑपरेशन में लगे अफसरों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेंगे।

इसी क्रम में नक्सलियों को चौतरफा घेरने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय में नक्सल मामलों के सलाहकार विजय कुमार ने सुकमा और डीजी नक्सल ऑपरेशन डीएम अवस्थी ने बीजापुर में डेरा डाल दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के डीजी शरद कुमार की गोपनीय रिपोर्ट के बाद विजय कुमार को तीन दिन में दूसरी बार छत्तीसगढ़ भेजा गया है।

सुकमा और बीजापुर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारियों की करीब दो घंटे तक चली बैठक में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान के लिए नया ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन को तेज करने के लिए सड़क निर्माण में लगे जवानों को वापस बुला लिया गया है। नक्सल विरोधी अभियान के आला अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन तेज करने के लिए सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सड़क का काम फिलहाल बंद किया गया है। बताया जा रहा है कि केंद्र से भी ऑपरेशन पर फोकस करने का निर्देश मिला है। डीजी नक्सल ऑपरेशन अवस्थी ने साफ किया कि बस्तर में सड़क निर्माण का कार्य सबसे बड़ा ऑपरेशन है। सीआरपीएफ ने सड़क सुरक्षा से इन्कार नहीं किया है, बल्कि यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से रणनीतिक उपाय है।

सुकमा के जंगलों में उतरे साढ़े आठ हजार जवान

नक्सल मोर्चे पर तैनात आला अधिकारियों ने बताया कि सुकमा में साढ़े आठ हजार जवानों को मोर्चे पर उतार दिया गया है। पहले चरण में ये जवान सिर्फ सूचना एकत्र करेंगे और कैंप को इनपुट भेजेंगे। इनके इनपुट के आधार पर अगले एक-दो दिन में बड़ा ऑपरेशन प्लान किया जा सकता है। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

एसबीआई एटीएम से निकले 500 के नोट से गांधी की तस्वीर गायब

भोपाल

मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में मुरैना में एसबीआई के एटीएम से बिना गांधीजी की तस्वीर वाला 500 का नोट निकला है। मुरैना जिले में एसबीआई के ब्रांच से ऐसे नोट निकले हैं। बताया जा रहा है कि इलाके के गोवर्धन शर्मा शुक्रवार रात शहर के एक एसबीआई एटीएम गए तो वहां से उनको जो नोट मिले उसमें गांधीजी की तस्वीर नहीं थी। उसने यह जानकारी गार्ड को दी और उसने एटीएम में मौजूद नंबर पर कॉल किया। इसके बाद गोवर्धन ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। उनसे बैंक ने कहा कि इस मामले को सिर्फ आरबीआई ही देख सकती है।

संघ के काम से रतन टाटा भी हैं प्रभावित - गडकरी

मुंबई

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम देखकर देश के प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने दी।

गडकरी मुंबई के मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभागार में संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक रमेशभाई मेहता के पुस्तक विमोचन समारोह में बोल रहे थे। विश्व का अद्वितीय संगठन: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' नामक इस पुस्तक का विमोचन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक ने किया। इस अवसर पर गडकरी ने कहा कि कुछ वर्ष पहले औरंगाबाद में संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार के नाम पर बने एक अस्पताल का उद्घाटन उद्योगपति रतन टाटा से करवाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। शुरू में रतन टाटा इस कार्यक्रम में जाने से झिझक रहे थे। लेकिन वहां पहुंचने पर वह संघ का काम देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उस अवसर पर रतन टाटा ने कहा कि वह सोच भी नहीं सकते कि संघ सेवा के इतने अच्छे काम कर रहा है। इस अवसर पर पुस्तक की चर्चा करते हुए उप्र के राज्यपाल राम नाइक ने कहा कि एक साथ चार भाषाओं में प्रकाशित इस पुस्तक के प्रथम कुछ अध्यायों को ही पढ़कर कहा जा सकता है कि आरएसएस दुनिया का एक अद्वितीय संगठन है।

सत्ता में एक बार फिर वापसी करेगी कांग्रेस - ए के एंटनी

तिरुअनंतपुरम

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी पार्टी के भविष्य को लेकर अभी उम्मीद नहीं हारे हैं। उन्हें भरोसा है कि कांग्रेस फिर सत्ता में वापसी करेगी। पूर्व रक्षा मंत्री का कहना है कि कांग्रेस वापसी करने में सक्षम है।

इतना ही नहीं हर कोई चाहता है कि वह देश में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष की अगुआई करे। बकौल एंटनी, वापसी करने की हमारे अंदर ताकत है। पहले भी हम ऐसी स्थितियों (चुनावों में हार) का सामना कर चुके हैं। यह कोई नहीं बात नहीं है। चुनावों में करारी हार के बाद सत्ता में वापसी करने का कांग्रेस का इतिहास रहा है। तिरुअनंतपुरम में पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के बाद वह पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य का कहना था कि वर्तमान समय में पार्टी के आधार को बढ़ाने की जरूरत है।

2024 से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो - नीति आयोग

नई दिल्ली

नीति आयोग ने 2024 से लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एकसाथ करवाने का सुझाव दिया है ताकि चुनाव प्रचार के कारण शासन व्यवस्था में पड़ने वाले व्यवधान को कम से कम किया जा सके। इस संबंध में विस्तृत जानकारी का उल्लेख करते हुए नीति आधारित इस थिंक टैंक ने कहा कि इस प्रस्ताव को लागू करने से अधिकतम एक बार कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल में कुछ कटौती या विस्तार करना पड़ सकता है।आयोग ने चुनाव आयोग को इस पर गौर करने को कहा और एकमुश्त चुनावों का रोडमैप तैयार करने के लिए संबंधित पक्षकारों का एक कार्यसमूह गठित करने का सुझाव दिया।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एकसाथ करवाने की वकालत कर चुके हैं। इस संबंध में 6 महीने के अंदर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना है और इसका अंतिम खाका अगले मार्च तक तैयार होगा। इस मसौदा रिपोर्ट को 23 अप्रैल को नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों के बीच प्रसारित किया गय था। इन सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य लोग शामिल हैं। यह सिफारिश इस लिहाज से अहम है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एकसाथ करवाने की वकालत कर चुके हैं। नीति आयोग की मसौदा रिपोर्ट कहती है कि भारत में सभी चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और समकालिक तरीके से होने चाहिए ताकि शासन व्यवस्था में प्रचार मोड के कारण होने वाला व्यवधान कम से कम किया जा सके।

हम वर्ष 2024 के चुनाव से इस दिशा में काम शुरू कर सकते हैं। इस साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुखर्जी ने अपने भाषण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एकसाथ करवाने की वकालत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी में एकमुश्त चुनाव करवाने की वकालत करते हुए कहा था कि एकसाथ चुनाव से सभी को कुछ नुकसान होगा। हमें भी नुकसान होगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे इस विचार को राजनीति के संकीर्ण चश्मे से न देखें।

वोटर्स को घूस देने वाले आरोपित उम्मीदवारों की सदस्यता रद्द की जाए - चुनाव आयोग

नई दिल्ली

मतदाताओं को लुभाने को लेकर जो उम्मीदवार आरोपपत्रों में नामजद हैं, चुनाव आयोग जल्द ही सरकार को उनकी सदस्यता पांच साल तक के लिए रद्द करने को कहेगा। तमिलनाडु विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए नए तरीकों के पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है।

आयोग में मौजूद सूत्रों ने बताया कि चुनाव निगरानी संस्था ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव की मांग करते हुए कानून मंत्रालय को पत्र लिखने का फैसला किया है। इसके पीछे यह उद्देश्य है कि अदालत में किसी उम्मीदवार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल होने के बाद उसे पांच साल तक के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया जाए। इस महीने की शुरुआत में आयोग ने जब पाया कि आरके नगर विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन का इस्तेमाल किया गया, तब आयोग ने उपचुनाव अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया था। उपचुनाव 12 अप्रैल को होना था। जे जयललिता की मृत्यु के बाद तमिलनाडु विधानसभा की इस सीट पर उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी थी।

अपने लंबे आदेश में आयोग ने इस बात की ओर इशारा किया था कि राजनीतिक पार्टियों और उनके शीर्ष नेताओं ने आरके नगर विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल किया ताकि चुनाव खर्च पर नजर रख रहे कानून प्रवर्तन अधिकारियों को चकमा दिया जा सके। दरअसल, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकद, उपहार, टोकन, प्रीपेड फोन रिचार्ज कूपन, अखबारों का सब्सक्रिप्शन, दूध का टोकन, बैंक खातों में धन का अंतरण और यहां तक कि मोबाइल नंबरों पर मोबाइल वैलेट भुगतान करने की शिकायतें चुनाव आयोग को मिली थी। इससे पहले, चुनाव आयोग ने सरकार से चुनाव कानून के तहत वह शक्तियां देने के लिए कहा है जहां वह धन के इस्तेमाल वाले चुनाव को रद्द कर सके। अभी आयोग सिर्फ बाहुबल के इस्तेमाल वाले चुनाव को रद्द कर सकता है। यह धन बल का इस्तेमाल होने पर किसी चुनाव को अनुच्छेद 324 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रद्द कर सकता है, लेकिन वह चाहता है कि यह शक्ति कानून के तहत निहित की जाए।

अंतरिक्ष में भी गूंजेगा पीएम का नारा 'सबका साथ सबका विकास'

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा से सबका साथ-सबका विकास के मंत्र को लेकर आगे बढने का प्रयास किया है और उसका यह मूलमंत्र सिर्फ देश के भीतर नहीं, बल्कि वैश्विक परिवेश और अड़ोस-पड़ोस के देशों के लिए भी है। मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा, भारत ने हमेशा सबका साथ-सबका विकास के मंत्र को लेकर आगे बढने का प्रयास किया है। जब हम सबका साथ-सबका विकास की बात करते हैं तो वो सिर्फ भारत के अंदर के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक परिवेश और खासकर हमारे अड़ोस-पड़ोस के देशों के लिए भी है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस के देशों का साथ भी हो, हमारे अड़ोस-पड़ोस के देशों का विकास भी हो। प्रधानमंत्री ने कहा, पांच मई को भारत दक्षिण एशिया उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। इस उपग्रह की क्षमता तथा इससे जुड़ी सुविधाएं दक्षिण एशिया की आर्थिक और विकासात्मक प्राथमिकताओं को पूरा करने में काफी मदद करेगा। यह हमारे पूरे क्षेत्र के आगे बढ़ने में मददगार होगा।

जम्मू में अमित शाह की आरएसएस के साथ बैठक
कश्मीर के हालात खराब करने वालों पर हुई चर्चा

जम्मू

जम्मू के दो दिवसीय दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार सुबह आरएसएस के साथ बैठक में जम्मू कश्मीर की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा की। अमित शाह सुबह नौ बजे के करीब जम्मू में आरएसएस मुख्यालय वीरभवन पहुंचे। सूत्रों के अनुसार बैठक में कश्मीर के हालात खराब करने के लिए देश विरोधी तत्वों के प्रयासों पर भी चर्चा हुई।

कश्मीर में पत्थरबाजी, छात्रों के उग्र प्रदर्शन से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। ऐसे में देश विरोधी तत्वों की शह पर घाटी में सुरक्षाबलों का मनोबल गिराने के लिए भी लगातार साजिशें हो रही हैं। कश्मीर में देश विरोधी तत्वों को शह देने की राजनीति से भी स्थिति बद से बदतर हो रही है। ऐसे में आठ मई से श्रीनगर में राज्य सरकार का दरबार खुलने के बाद स्थिति को खराब करने की कोशिशें होना तय है। सूत्रों के अनुसार इन मुद्दों के साथ बैठक में जम्मू संभाग में राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत बनाने के लिए हो रही कोशिशों के साथ राजनीतिक हालात व भाजपा-पीडीपी सरकार के कामकाज, भाजपा के मंत्रियों, विधायकों की भूमिका पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार अमित शाह से हुई इस बैठक में प्रांत संघचालक ब्रिगेडियर सुचेत सिंह, प्रांत प्रचारक रमेश पप्पा, प्रांत कार्यवाहक पुरषोत्तम दधीचि ने हिस्सा लिया। अमित शाह के साथ इस मौके पर भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कौल भी मौजूद थे। इसी बीच आरएसएस के पदाधिकारियों से बैठक के बाद अमित शाह भाजपा मुख्यालय में लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए रवाना हो गए।

केंद्र सरकार ने किया डीजल वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध का विरोध

नई दिल्ली

सरकार ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का दस साल के लिए दिल्ली-एनसीआर में डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करना कानून और प्राधिकार के क्षेत्र का उल्लंघन है। कानून और प्राधिकरण के लिहाज से वाहनों की परिचालन समय-सीमा तय करने का अधिकार केवल कार्यपालिका का है।

केंद्र सरकार ने एनजीटी के लगाए प्रतिबंध के तीन महीने बाद इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना विरोध स्पष्ट कर दिया है। केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक दशक से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया जाए।

लिहाजा, भारी उद्योग मंत्रालय ने एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व वाली खंडपीठ को बताया कि ट्रिब्यूनल का यह आदेश कानून के प्रावधानों के परे चला गया है।

चूंकि यह आदेश बिना किसी जांच के दस साल से अधिक समय पहले खरीदे दिल्ली-एनसीआर के सभी डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करता है। केंद्र ने अपने लिखित जवाब में कहा कि वाहनों की आयु तय करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, जिसे एक गजट के जरिए अधिसूचित किया गया है। इसलिए एनजीटी का यह आदेश मोटर वेहिकल एक्ट का भी उल्लंघन है। चूंकि मोटर वेहिकल एक्ट में बताया गया है कि प्रतिबंध संबंधी फैसला लेते हुए अधिकृत प्रशासन को यह साफ करना होगा कि वाहन जनता के लिए खतरा है और इसकी अब कोई मरम्मत नहीं हो सकती।

एनजीटी के आदेश को चुनौती देते हुए मंत्रालय ने कहा कि किसी वाहन का रेजिस्ट्रेशन रद करना केवल मोटर वेहिकल एक्ट के तहत वाहन के मालिक को नोटिस देकर ही हो सकता है। वह भी तब जबकि इस दावे की पुष्टि हो सके कि वाहन सड़क पर चलने लायक नहीं है या उसकी मरम्मत नहीं हो सकती।

मंत्रालय ने इस बात की भी दलील दी कि एनजीटी का फैसला इस लिहाज से भी गलत है कि उसे लागू करने का दायरा बहुत बड़ा है। दिल्ली-एनसीआर में वाहनों की संख्या अत्यधिक है क्योंकि यह दिल्ली के साथ ही उससे लगे हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों को भी कवर करता है।

श्रीनगर : खान्यार पुलिस स्टेशन के बाहर ग्रेनेड हमला, एक की मौत

श्रीनगर

जम्मू कश्मीर में लगातार सुरक्षाकर्मी और पुलिस बलों को निशाना बनाया जा रहा है। रविवार को श्रीनगर के खान्यार पुलिस स्टेशन के पास हुए ग्रेनेड से हमला किया गया। इस ग्रेनेड हमले में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि तीन पुलिसकर्मी समेत चार लोग घायल हुए हैं। ग्रेनेड हमले में घायल हुए लोगों को पास के अस्पताल में भर्ता कराया गया है जहां पर उन सभी को शुरूआती उपचार कराया जा रहा है। लेकिन, जिस तरह से वहां पर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं उसने एक चिंता जरूर खड़ी कर दी है।